

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-1980/2011/भीलवाड़ा

...अपीलार्थी

मै० असगर खान भीलवाड़ा।

बनाम

1. उपयुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा
 2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लिजिंग टैक्स, भीलवाड़ा
- ...प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

लिखित बहस प्राप्त
द्वारा श्री एम.पी.शर्मा कर सलाहकार
श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक

...अपीलार्थी की ओर से

...प्रत्यर्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक : 24.04.2017

निर्णय

1. उपर्युक्त अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, भीलवाड़ा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 82 में पारित किये गये आदेश दिनांक 02.08.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 12.03.2010 को निरस्त करते हुए दिशा निर्देशों के साथ प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया है। जिनका विवरण निम्न तालिका अनुसार है :-
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी ठेकेदारी का कार्य करता है तथा उसके द्वारा वर्ष 2007-08 हेतु प्रस्तुत विवरणियों के आधार पर ई. सी. पर आधारित प्राप्तियां 97,59,488/- रु., लेबर वर्क 20,410/- रु. व बिना ई.सी. पर आधारित प्राप्तियां 34,62,58/- रु. थी। कर निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 12.03.2010 द्वारा कर निर्धारण किया जिसके विरुद्ध व्यवहारी ने अधीनस्थ न्यायालय उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई तथा अपील में विवादित टर्न ओवर पर निर्धारित कर 39,982/- रु. व शास्ति राशि रु. 2000/- को विवादित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश द्वारा निम्न प्रकार निर्णय पारित किया गया है :-

(1). कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी की घोषित खरीद को अमान्य कर बिक्री बढ़ाकर करारोपण किया है, एवं अपंजीकृत व्यवहारी से अनुमानित खरीद मानी है, जिसका कोई विशिष्ट नोटिस जारी नहीं किया गया। इस बिन्दु पर प्रकरण इस निर्देश के साथ कर निर्धारण को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि

23/

लगातार.....2

व्यवसाई द्वारा घोषित बिक्री में वृद्धि करने से पूर्व विस्तृत एवं विशिष्ट नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः आदेश पारित किया जावे। विद्वान अभिभाषक द्वारा माननीय न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं, जो इस प्रकरण में भिन्न तथ्यों के कारण लागू नहीं होते हैं।

(2). कर निर्धारण अधिकारी को ई.सी. कार्यों में लेबर 25 प्रतिशत कर करके ई.सी. फीस आरोपित करनी चाहिये थी जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसा नहीं किया गया। व्यवहारी को ई.सी. हेतु आप्शन दिया हुआ है। यदि वह ई.सी. लेना चाहता है तो कुल प्राप्तियों पर उसको ई.सी. फीस देनी होगी, लेबर की कटौतियां किया जाना प्रावधानों के अनुसार नहीं है अतः इस बिन्दु पर अपील अस्वीकार की जाती है। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा माननीय न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं, जो इस प्रकरण में भिन्न तथ्यों के कारण लागू नहीं होते हैं।

(3). अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि रिटर्न समय पर पेश नहीं करने का कारण अवार्डर द्वारा प्रमाण पत्र जारी नहीं किये गये हैं। कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा रिटर्न विलंब से प्रस्तुत करने पर धारा 58 के तहत रु. 2000/- की शासित आरोपित की है तथा शास्ति आरोपण से पूर्व व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर भी नहीं प्रदान किया गया अतः इस बिन्दु पर प्रकरण प्रपिप्रेषित किया जाता है कि व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जावे और इस बिंदु पर कर निर्धारण अधिकारी अपने स्तर पर जांच करे तथा जांच उपरांत निर्णय के लिये स्वतंत्र हैं।

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के उपरोक्त निर्णय से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से उनके कर सलाहकार ने लिखित बहस प्रस्तुत की। लिखित बहस में कथन किया गया कि विवादित मामला कर निर्धारण वर्ष 2007-08 का है जिसका वर्ष सुनवाई का विशिष्ट नोटिस अब नहीं दिया जा सकता क्योंकि कर निर्धारण की समय सीमा 31.03.2010 को समाप्त हो चुकी है। ई.सी. फीस पर किये गये कार्य पर मजदूरी राशि बिलडिंग कार्य होने से 25 प्रतिशत की मजदूरी कम करने के पश्चात् ही ई.सी. फीस आरोपित करनी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय में इन्होंने अपने समर्थन में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत (1999) 114 एसटीसी 265 प्रस्तुत किया है। ई.सी. कार्य में वेट-7 के इनपुट का 44,828/- रु. का समायोजन भी नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

27-

लगातार.....3

5. बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। अतः निगरानी खारिज की जावे।
6. उभयपक्ष की बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार हैं :-
7. अपीलार्थी का अपील में प्रथम मुख्य आधार यह है कि ई.सी. फीस पर किये गये कार्य पर मजदूरी राशि बिलडिंग कार्य होने से 25 प्रतिशत की मजदूरी कम करने के पश्चात् ही ई.सी. फीस आरोपित करनी चाहिए थी व साथ ही ई.सी. कार्य में वेट-7 के इनपुट का 44,828/- रु. का समायोजन भी नहीं दिया है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में उद्धरित न्यायिक दृष्टांत अधोहस्ताक्षरी के विनम्र मत में इस प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या F.12 (63)/FD/Tax 2005-80 dt. 11-08-2006 में जिन कार्य संविदाओं का उल्लेख सूची में किया जाकर ऑटोमेटिक मुक्ति शुल्क जो विहित किया गया है, वह कुल कार्य संविदा मूल्य (Total value of work contract) पर है जबकि माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष विवादित बिन्दु कर्नाटक राज्य के विक्रय कर अधिनियम, 1957 की धारा 17(6) के प्रावधान जो दिनांक 01.04.1996 से पूर्व में विद्यमान थे, का निर्वचन था, जिसमें सकल पण्यावर्त, जो कार्य संविदा निष्पादन के दौरान के वस्तुओं या अन्य रूप में माल सम्पत्ति के रूप में अन्तरित हुयी हो, का उल्लेख था, परन्तु राज्य सरकार द्वारा जारी ऊपर उद्धरित अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 में विशेष रूप से कुल कार्य संविदा मूल्य (Total value of work contract) पर ऑटोमेटिक मुक्ति शुल्क की दर अधिसूचित की गयी है। इस संबंध में अधिसूचना दिनांक 29.03.2001 का मूल पठन इस प्रकार है:-

S.No 2130 : F.12 (63)/FD/Tax 2005-80 dt. 11-08-2006

In exercise of the powers conferred by section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts from payment of tax the registered dealers engaged in execution of works contracts leviable on the transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of works contract (s) subject to the following conditions, namely:-

1. That in case of works contracts,

(i) awarded on or after 01.04.2006, the contractor shall apply in form WT-1; and

(ii) where the contractor opted for automatic exemption fee under rule 12 of Rajasthan Sales Tax Rules, 1995 shall apply for exemption under this notification for the remaining part of the contract as on April 1, 2006, in form WT-2.

2. That application shall be submitted [within 60 days] from the date of award of the contract or the date of issue of this notification, whichever is later,

271-

लगातार.....4

3. That in case of delayed submission of the application, the assessing authority may, after recording reasons for doing so, condone the delay, on payment of a later fee of rupees one thousand for a year or part thereof. [However, delay in case of second year or part thereof can be condoned on payment of a late fee of rupees five thousand and no application shall be entertained after expiry of two year from the date of award of the contracts]

4. That on receipt of the application under clause (1), the assessing authority on being satisfied as to the correctness of the facts mentioned therein, shall issue exemption certificate in form WT-3 appended hereto, in the case of works contracts awarded on or after 1.4.2006 and in form WT-4 appended hereto, in the case of work contracts, where the contractor opted for automatic exemption fee under rule 12 of Rajasthan Sales Tax Rules, 1995 for exemption, for the remaining part of the contract as on 01.04.2006. A copy thereof, shall be sent to the awarder.

5. That such contractor shall pay exemption fee at the rate specified in Column 3 of the list given below in the following manner:-

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts from payment of tax the registered dealers engaged in execution of works contracts leviable on the transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of works contract (s) subject to the following conditions, namely:-

- (iv) Where an awarder is a Department of any Government a Corporation, a public undertaking a co-operative society, a local body, a statutory body, an autonomous body, a trust or a private or public limited company, an amount calculated at the rate as specified in column no. 3 of the list given below shall be deducted by such awarder from each bill of payment to made in any manner to such contractor and all the provisions of payment of tax provided in the Act or the rules made there under for works contractors shall mutatis mutandis apply. In case the contractor has already received some payments for execution of works contract from the awarder before filing application, he shall enclose proof of payment/deduction of notified exemption fee on such payments, along with interest, if any, up to the date of filing of application, under this notification;
- (v) Where the awarder is not covered under sub-clause (i) above, the contractor shall be required to make payment of exemption fee in equal monthly installments in a period not exceeding the period of contract from the date of filing of application. In case the contractor has already received some payments for execution of works contract from the awarder, he shall enclose proof of payment of notified exemption fee on such payments, along with interest up to the date of filing of application, under this notification;
- (vi) The amount already deducted by the awarder in lieu of tax from bills of payments to the dealer before the issuance of this notification shall be adjusted against the exemption fee;

२१-

लगातार.....5

(6) that the contractor shall not be entitled to claim input tax credit in respect of the goods used in execution of the works contract for which exemption certificate has been granted ;

(7) that the certificate of exemption shall be liable to be cancelled by the assessing authority retrospectively if it is found that the same has been issued under contravention of the provisions of the Act, rules or notification; and

(8) that the tax collected or charged, if any, by such dealer before the issue of this notification shall be deposited, to the State Government and tax so deposited shall not be refunded or adjusted against the exemption fee.

LIST

S.No.	Description of Works Contract	Rate of Exemption Fee % of the total value of the contract
1.	Works Contract relating to buildings, roads, bridges, dams, canals, sewerage system.	1.50%
2.	Works Contract relating to Installation of plants & Machinery including PSPO, water treatment plant, laying of pipe line with material.	2.25%
3.	Any other kind of works contract not covered by S.No. 2 & 3.	3.00%

उपरोक्त विधिक स्थित से स्पष्ट है कि ई.सी. फीस का संदाय संविदा में दर्शाई गई कुल राशि पर होगा तथा संविदा कार्य जिस पर ई.सी. फीस दी गई है, में प्रयुक्त माल के क्रय पर कोई इनपुट टैक्स देय नहीं होगा। इस प्रकार अपील का यह आधार भी स्वीकार योग्य नहीं है।

8. अपील में तृतीय मुख्य आधार यह है कि विवादित मामला कर निर्धारण वर्ष 2007-08 का है जिसका वर्ष सुनवाई का विशिष्ट नोटिस अब नहीं दिया जा सकता क्योंकि कर निर्धारण की समय सीमा 31.03.2010 को समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। इस न्यायालय के विनम्रमतानुसार समय सीमा 31.03.2010 तक थी तथा कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश इससे पूर्व दिनांक 12.03.10 को पारित कर दिया है तो इसके पश्चात् प्रकरण विभिन्न स्तरों पर न्यायिक कार्यवाही के दौरान विचाराधीन रहा है तो वह अवधि सीमा की गणना हेतु नहीं मानी जायेगी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण रिमाण्ड किया है तो इस आधार पर कार्यवाही समाप्त नहीं की जा सकती कि प्रकरण में समय सीमा समाप्त हो चुकी है।

27

9. इस प्रकार प्रकरण में ई.सी. पर किये गये कार्य पर देय कर की गणना कार्य आदेश में दर्शायी गयी राशि के आधार पर ही किया जाने का प्रावधान है तथा इसमें से मजदूरी राशि कम नहीं की जा सकती। संविदा कार्य जिस पर ई.सी. फीस दी गई है, में प्रयुक्त माल के क्रय पर कोई इनपुट टैक्स देय नहीं होगा।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन होने के कारण अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.08.2011 यथावत रखा जाता है। अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष दिनांक 22.05.2015 को उपस्थित हो।

11. निर्णय सुनाया गया।


(नत्थूराम)
सदस्य